की मात्रा 1966 और 1992 में क्रमशः 45.68 प्रतिशत और 25.32 प्रतिशत थी । जल विद्युत उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण इस अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किये जाने पर अधिक जोर दिया जाना रहा है ।

(घ) मार्च, 1992 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कुल मिलाकर 7832 मेगावाट क्षमता की 42 जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु निवेश संबंधी स्वीकृति के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर चुका है ।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

1265. **श्री विनोद शर्मा :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके देश में विद्युत उत्पादन करने के संबंध में समझौते किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने उद्यमों के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों के माध्यम से देश में कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय किया गया है तथा यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत दर में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का सरकार का निर्णय

1266. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने **विद्युत** दर में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत की दरों में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो जायगी तथा इससे देश के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के टैरिफ की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिये कि वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित निवल परिसंपत्तियों पर न्यूनतम सांविधिक 3% का अधिशेष अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके । टैरिफ का निर्धारण करना संबंधित बोर्ड/राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ग) और (घ) विद्युत टैरिफ में वृद्धि किये जाने के कारण औद्योगिक उत्पाद की लागत पर जो प्रभाव पड़ेगा यह भिन्न-भिन्न राज्य के लिये भिन्न-भिन्न होगा, क्योंकि अन्य निवेशों में विद्युत ही एक निवेश होता है और ऊर्जा सघन उद्योगों को छोड़कर सभी लागत घटकों में इस की औसत मात्रा 5% से 6× तक होती है । अतः लागत आधारित विद्युत टैरिफ से औद्योगिक उत्पाद और निर्यात सामग्री की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि होने की संभावना नहीं है ।

देश में "प्लांट लोड फैक्टर" की दर

1267. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "प्लांट लोड फैक्टर" की दर संतोष-जनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औसत दर क्या रही है ;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये यह दर निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में राष्ट्रीय स्तर पर "प्लांट लोड फैक्टर" की दर क्या होगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सातवीं योजना के विभिन्न वर्षों और 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात निम्नवत् रहा है:-

वर्ष	संयंत्र भार अनुपात (%)
1985-86	52.4
1986-87	53.2
1987-88	56.5
1988-89	55.0
1989-90	56.5
1990-91 (वार्षिक योजना)	53.8
1991-92 (वार्षिक योजना)	55.3

(ग) और (घ) विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को वर्ष दर वर्ष के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है और यह अधिष्ठापित क्षमता, अनुरक्षण संबंधी कार्यक्रम, संयंत्र के प्रचालन की अवधि, कोयले की गुणवत्ता एवं इसकी उपलब्धता और अन्य तकनीकी/प्रणालीगत बाधाओं आदि पर निर्भर करता है ।

Proposal to Transfer the Badarpur Thermal Power Station from N.T.P.C. to DESU

1268. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government propose to transfer the Badarpur Thermal Power Station from the control of the NTPC to the DESU; and

(b) if so, what are the details thereof and also the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) There is no proposal for the present to transfer Badarpur Thermal Power Station to D.E.S.U.

(b) Does not arise in view of reply to part(a) of the question above.

Kutir Jyoti Programme in Bihar

1269. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Bihar State Electricity Board had declined to take up the Kutir Jyoti Programme revived from the "Centre", recently;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the names of the State Electricity Boards which have to take up the above programme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) The Bihar State Electricity Board has informed that they are not considering to continue the Kutir Jyoti Scheme.

(c) So far State Electricity Boards/Power Departments of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Manipur, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura and West Bengal have expressed their willingness to revive the Kutir Jyoti Programme.